उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण

*डॉ. मुसव्विर अहमद

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक महत्वपूर्ण नीति है, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारना और उसे विश्वस्तरीय बनाना है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य है भारतीय शिक्षा को आधुनिकीकरण करना, गुणवत्ता में सुधार करना, और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए बेहतर मौके प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में संशोधित की गई थी। तब से कई बदलाव हुए हैं जिनके लिए नीति में संशोधन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ,21 वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और चौंतीस साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 की जगह लेती है। यह नीति पहुंच, समानता, गुणवत्ता ,सामर्थ्य और जवाबदेही के मूलभूत स्तंभों पर निर्मित है । यह नीति सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे से जुड़ी है और इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज शिक्षा दोनों को अधिक समग्र, लचीला, बहु–विषयक, 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल बनाकर भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

संकेताक्षर : समानता, समावेशी उत्तम शिक्षा, विनियमन, परामर्श मिशन, अकादमिक क्रेडिट।

परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के साथ ही भारत की शिक्षा प्रणाली में भी 21वीं शताब्दी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप बदलावों का अहम सिलसिला शुरू हो गया है। इस नीति में पठन–पाठन की पुरानी चली आ रही शिक्षक आधरित व्यवस्था की जगह विद्यार्थी–केन्द्रित नई व्यवस्था लाकर समूची प्रणाली में बदलाव लाने पर ज़ोर दिया गया है जिससे विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके और उनकी रचनात्मक क्षमता भी विकसित की जा सके। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के इस मूल सिद्धान्त पर विशेष बल दिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के साक्षर बना देने और उन्हें अंक ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए या फिर विद्यार्थियों में विवेचनात्मक सोच और समस्या का समाधान खोजने तक ही सीमित न रहे बल्कि शिक्षा से सामाजिक और भावनात्मक कौशल का विकास भी हो, इन्हें सॉफ्रट स्किल्स कहा जाता है और इनमें सांस्कृतिक चेतना और अनुभूति, देने की क्षमता और वास्तविक जीवन में गणित से गुणा–भाग और जमा–घटा कर पाने की क्षमता के विकास पर बल दिया गया है। इसी उद्देश्य से निपुण भारत मिशन शुरू किया गया है ताकि हर बच्चे के लिए ऐसा परिवेश बन जाए कि आने वाले पांच वर्ष में वह कक्षा तीन तक के स्तर की पढ़ने–लिखने की क्षमता और गणित का ज्ञान प्राप्त कर ले। आकलन प्रक्रिया निरंतर चलाए रखने से यह समझ में आता जाएगा कि बच्चे किस प्रकार सोचते और सीखते हैं और इसे ध्यान में रखकर ही एनईपी 2020 में कई बुनियादी सुधार शामिल किए गए हैं जिनकी मदद से विद्यार्थियों के आकलन की प्रक्रिया के तौर–तरीकों, प्रारूप और क्रियान्वयन को नया रूप दिया जा सकेगा। नीति में बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव लाकर उन्हें और प्रामाणिक बनाना, बच्चों पर पुस्तकों का बोझ कम करने और कोचिंग की व्यवस्था समाप्त करने पर

खास ज़ोर दिया गया है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और संस्थानों की क्षमता के निर्माण पर भी बल दिया जा रहा है। संस्थानों में विविध विषय रहेंगे और शिक्षा विज्ञान में भी परिवर्तन लाए जाएंगे जिससे बच्चों को विषय चुनने के अधिक विकल्प प्राप्त होंगे। ऐसी भी उम्मीद है कि सहायता प्राप्त कॉलेज धीरे–धीरे बंद किए जाएंगे और वर्ष 2035 तक उनकी जगह अनेक विषयों की शिक्षा देने वाले संस्थान आ जाएंगे। सभी को शिक्षकों की अहम भूमिका के बारे में पता है। नई शिक्षा नीति में सुझाव है कि शिक्षकों को स्वयं में सुधार लाने और अपने अध्यापन कार्य से जुड़ी नई जानकारियां प्राप्त करने के वास्ते निरंतर प्रशिक्षण के अवसर मिलने चाहिए। इसी कारण शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था को भी नई परिस्थितियों और बदलते परिवेश के अनुरूप मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। सभी के लिए समानता पर आधारित और समावेशी उत्तम शिक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था कराने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में शिक्षा तक सबकी पहुंच, सभी की भागीदारी और शिक्षण स्तर के मामले में विभिन्न वर्गों के बीच अंतर को समाप्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस नीति में समानता को ही समावेशी व्यवस्था का आधार माना गया है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष बल दिया गया है। यह नीति अपने प्रारूप और आशय दोनों के ही आधार पर वैश्विक भी है और स्थानीय भी। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की सुदृढ़ नींव तैयार करके उनकी शिक्षा आवश्यकताएं पूरी करने को प्रमुखता दी गई है ताकि भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व नेता के रूप में उभर कर सामने आए।

उच्च शिक्षा के संदर्भ में एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएं

(1) 2035 तक जीईआर को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना एनईपी 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत (2018) से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी।

(2) समग्र बहुविषयक शिक्षा व्यापक आधारित बहु–विषयक, लचीले पाठ्यक्रम के साथ समग्र यूजी शिक्षा, विषयों का रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और उचित प्रमाणीकरण के साथ कई प्रवेश और निकास बिंदु। विभिन्न HEI से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जानी है ताकि इन्हें स्थानांतरित किया जा सके और अर्जित अंतिम डिग्री में गिना जा सके। आईआईटी, आईआईएम के बराबर बहु–विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) को देश में वैश्विक मानकों के सर्वोत्तम बहु–विषयक शिक्षा के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा।

(3) विनियमन भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) को चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर, संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एक एकल व्यापक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह प्रौद्योगिकी के माध्यम से फेसलेस हस्तक्षेप के माध्यम से कार्य करेगा, और इसमें मानदंडों और मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले HEI को दंडित करने की शक्तियां होंगी। सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थान विनियमन, मान्यता और शैक्षणिक मानकों के लिए समान मानदंडों द्वारा शासित होंगे।

(4) तर्कसंगत संस्थागत वास्तुकला उच्च शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक जुड़ाव प्रदान करने वाले बड़े, अच्छी तरह से संसाधनयुक्त, जीवंत बहु–विषयक संस्थानों में बदल दिया जाएगा। कॉलेजों की संबद्धता को 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है और कॉलेजों को श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरण–वार तंत्र स्थापित किया जाना है।

(5) प्रेरित, ऊर्जावान और सक्षम संकाय स्पष्ट रूप से परिभाषित, स्वतंत्र, पारदर्शी भर्ती के माध्यम से संकाय को प्रेरित करने, सक्रिय करने और क्षमता निर्माण के लिए सिफारिशें।

(6) अध्यापक शिक्षा शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफटीई 2021: एनसीईआरटी के परामर्श से एनसीटीई द्वारा एक नई और व्यापक रूपरेखा तैयार की जाएगी।

(7) परामर्श मिशन परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें उत्कृष्ट वरिष्ठ/सेवानिवृत्त संकाय का एक बड़ा समूह शामिल होगा – जिसमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता वाले लोग भी शामिल होंगे।

(8) छात्रों के लिए वित्तीय सहायता एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य एसईडीजी से संबंधित छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएंगे। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन, बढ़ावा देने और ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा।

(9) मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह उच्चतम गुणवत्ता वाले इन–क्लास कार्यक्रमों के बराबर है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल रिपॉजिटरी, अनुसंधान के लिए वित्त पोषण, बेहतर छात्र सेवाएं, एमओओसी की क्रेडिट–आधारित मान्यता आदि जैसे उपाय किए जाएंगे।

(10) ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों की ई–शिक्षा आवश्यकताओं की देखभाल के लिए एमएचआरडी में डिजिटल बुनियादी ढांचे, डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण के लिए एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी।

(11) शिक्षा में प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (एनईटीएफ): सीखने, मूल्यांकन, योजना और प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय बनाया जाएगा।

(12) व्यावसायिक शिक्षा सभी व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगी। स्टैंड–अलोन तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालय आदि का लक्ष्य बहु–विषयक संस्थान बनने का होगा।

(13) प्रौढ़ शिक्षा नीति का लक्ष्य 100 प्रतिशत युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना है।

(14) वित्त पोषण शिक्षा केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द जीडीपी के 6 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे।

क्षेत्रीय भाषा में उच्च शिक्षा के सकारात्मक पहलू

विषय–विशिष्ट सुधार: भारत और अन्य एशियाई देशों में कई अध्ययन अंग्रेजी माध्यम के बजाय क्षेत्रीय माध्यम का उपयोग करने वाले छात्रों के सीखने के परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव का सुझाव देते हैं। विशेष रूप से विज्ञान और गणित में अंग्रेजी की तुलना में अपनी मूल भाषा में पढ़ने वाले छात्रों का प्रदर्शन बेहतर पाया गया है । भागीदारी की उच्च दर: मूल भाषा में अध्ययन करने से छात्रों में उच्च उपस्थिति, प्रेरणा और बोलने के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है और मातृभाषा से परिचित होने के कारण अध्ययन में माता– पिता की भागीदारी और समर्थन में सुधार होता है । सकल–नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि: इससे अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि होगी। इससे भाषा–आधारित भेदभाव को रोकने में भी मदद मिलेगी।

नीति से संबंधित मुद्दे

1) एकीकरण का अभाव सोच और दस्तावेज़ दोनों में, प्रौद्योगिकी और शिक्षाशास्त्र के एकीकरण जैसे अंतराल हैं। आजीवन सीखने जैसे बड़े अंतराल हैं, जो उभरते विज्ञानों में उन्नयन का एक प्रमुख तत्व होना चाहिए था।

2) भाषा अवरोध दस्तावेज़ में बहुत कुछ बहस के लिए उपयुक्त है – जैसे कि भाषा। एनईपी सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कक्षा पांच तक घरेलू भाषा में सीखने को सक्षम बनाना चाहता ळें लेकिन यह भी सच है कि शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता है और भारत में गतिशीलता की भाषा अंग्रेजी है।

3) बहुभाषावाद बहस घरेलू भाषा उन जगहों पर सफल होती है जहां पारिस्थितिकी तंत्र उच्च शिक्षा और रोजगार तक फैला हुआ है। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के बिना, यह काफी अच्छा नहीं हो सकता है। एनईपी बहुभाषावाद की बात करता है और इस पर जोर दिया जाना चाहिए। भारत में अधिकांश कक्षाएं वास्तव में द्विभाषी हैं।

4) धन की कमी आर्थिक सर्वेक्षण 2019–2020 के अनुसार, शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च (केंद्र और राज्य द्वारा) सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत था। शिक्षा की लागत संरचना में बदलाव अपरिहार्य है।

5) अतिमहत्वाकांक्षीउपरोक्त सभी नीतिगत कदमों के लिए भारी संसाधनों की आवश्यकता होती है। सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत पर सार्वजनिक व्यय का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान कर–से–जीडीपी अनुपात और स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों के राष्ट्रीय खजाने पर प्रतिस्पर्धी दावों को देखते हुए, यह निश्चित रूप से एक लंबा आदेश है।

6) शैक्षणिक सीमाएँ दस्तावेज़ लचीलेपन, विकल्प, प्रयोग के बारे में बात करता है। उच्च शिक्षा में, दस्तावेज़ मानता है कि शैक्षणिक आवश्यकताओं की विविधता है।

8) संस्थागत सीमाएँ एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली में संस्थानों की विविधता शामिल होगी, न कि मजबूरन बहु–अनुशासनात्मक प्रणाली। छात्रों के पास विभिन्न प्रकार के संस्थानों का विकल्प होना चाहिए। यह नीति केंद्र से अनिवार्य एक नई तरह की संस्थागत समरूपता पैदा करने का जोखिम उठाती है।

9) परीक्षाओं से संबंधित मुद्दे प्रतिस्पर्धा के कारण परीक्षाएँ विक्षिप्त अनुभव हैं; प्रदर्शन में थोड़ी सी गिरावट के परिणाम अवसरों की दृष्टि से बहुत बड़े होते हैं। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण संस्थानों तक पहुंच और उन संस्थानों तक पहुंच के परिणामस्वरूप आय के अंतर दोनों के मामले में कम असमान समाज की आवश्यकता होगी।

आगे बढ़ने का रास्ता

इस महत्वाकांक्षी नीति की एक कीमत चुकानी पड़ती है और बाकी बातें इसके अक्षरशः कार्यान्वयन पर निर्भर करती हैं।

- नीति की भावना और इरादे का कार्यान्वयन सबसे महत्वपूर्ण मामला है।
- नीतिगत पहलों को चरणबद्ध तरीके से लागू करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक नीति बिंदु में कई चरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक को पिछले चरण को सफलतापूर्वक लागू करने की आवश्यकता होती है।
- नीतिगत बिंदुओं की इष्टतम अनुक्रमण सुनिश्चित करने में प्राथमिकता महत्वपूर्ण होगी, और सबसे महत्वपूर्ण और तत्काल कार्रवाई पहले की जाएगी, जिससे एक मजबूत आधार सक्षम हो सके।

- इसके बाद, कार्यान्वयन में व्यापकता महत्वपूर्ण होगी; चूँकि यह नीति परस्पर जुड़ी हुई और समग्र है, केवल पूर्ण कार्यान्वयन, टुकड़ों में नहीं, यह सुनिश्चित करेगा कि वांछित उद्देश्य प्राप्त हो जाएं।
- चूंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, इसलिए इसे केंद्र और राज्यों के बीच सावधानीपूर्वक योजना, संयुक्त निगरानी और सहयोगात्मक कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी।
- नीति के संतोषजनक कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर अपेक्षित संसाधनों – मानव, ढांचागत और वित्तीय – का समय पर समावेश महत्वपूर्ण होगा।
- अंत में, सभी पहलों का प्रभावी सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए कई समानांतर कार्यान्वयन चरणों के बीच संबंधों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और समीक्षा आवश्यक होगी।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को सुधारने और बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका प्रमुख परिणाम यह होगा कि बच्चे और युवा अब बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके पेशेवर विकास और देश की सामाजिक और आर्थिक समृद्धि में सहयोग मिलेगा। तथापि, इसे सफल बनाने के लिए चुनौतियों का सामना करना होगा और सुनिश्चित किया जाना होगा कि नीति के प्रावधानों को प्रैक्टिकल रूप से अमल में लाया जा रहा है।

***सहायक आचार्य**
उर्दू विभाग
शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह
राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राज.)

संदर्भ ग्रंथ

1. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1656573
2. आर्थिक–समीक्षा 2019–20, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
3. https://nep2020.hinsoli.com/2020/08/2020_96.html
4. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
5. योजना पत्रिका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, फरवरी 2022, वर्ष– 66, अंक–02, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
6. https://social.niti.gov.in/education-index
7. Nandini, ed. 29 July 2020, "New Education Policy-2020 Highlights: School and Higher Education to see Major Challenges". Hindustan Times.